(c) A statement is laid on the Table of the House. [See Appendix I, annexure No. 100].

Comptroller and Auditor-General of India

540. Shri Harish Chandra Mathur: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Comptroller and Auditor-General has full administrative control and financial powers over the establishments under him; and

(b) what are the limitations, if any, to which he is subjected?

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The Comptroller and Auditor-General has powers to the extent indicated in the statement laid on the Table which also mentions the restrictions, if any. [See Appendix I, annexure No. 101.]

In matters falling outside these delegated powers, sanction of the Government of India is necessary.

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

५४१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री डी० चं शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १३ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) इस कार्यकारी दल के कौन-कौन सदस्य हैं ; और

(ग) क्या जिन विश्वविद्यालयों ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देना प्रारम्भ किया है अथवा उसके लिये कार्यक्रम तैयार किया है उन के नाम, उन भाषाओं के नाम और उन वर्गों के नाम जिन के लिये भारतीय भाषाओं का माध्यम अपनाया गया है बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० डा० डा० कीमाली) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना का विवरण पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Facilities for Private Litigation to Government Employees

542. **Shri Ram Garib:**
Shri Basumatari:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether any facilities to the Class III and Class IV employees of the Central Government are extended by the Central Government in their private litigation;

(b) if so, what are those facilities;

(c) whether they have any proposal to set apart some Government advocates who will take up the cases of those employees at a concessional rate; and

(d) whether the Welfare Officers of the various Ministries of the Government of India give any assistance to the Class III and Class IV Central Government employees in their private litigation?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) No.

(d) Two.